726वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 726वीं बैठक दिनांक 21/02/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 11064/2023 Shri Ashish Gupta, Proprietor, R/o House No. 127, Mahu Neemuch Road, DRP Line ke Samne, District Mandsaur , MADHYA PRADESH, 458001, Prior Environment Clearance for Bhandariya Stone Quarry in an area of 0.3475 ha.(9000 cum per year) (Khasra No. 322/2), Village-Bhandariya, Tehsil-Daloda, District-Mandsaur (MP) (B2). T.P.</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 21/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Gupta, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ASHISH GUPTA, PROPRIETOR, House no.127, Mahu neemach Road, DRP line ke Samne Mandsaur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	322/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	0.3475 hectare.
स्थल	Village- Bhandariya, Tehsil- Daloda, District- Mandsaur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 1222 दिनांक	

	13/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	फार्म–1 अनुसार Blasting Is Not Needed (Mining will be carried out by using Drilling & Rock Breaker.)
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–9,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–9,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1337 दिनांक 21/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.3475 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1337 दिनांक 21/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1337 दिनांक 21/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सगवाली जिला मंदसौर के पत्र दिनांक 03/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1337 दिनांक 21/09/23 अनुसार उक्त खदान को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान को अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित है। गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 364 मी. पर एवं उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 492 मी. की दूरी पर पवन चक्की स्थापित है, पूर्व दिशा में लगभग 254 मी की दूरी पर कच्चा रोड एवं पश्चिम दिशा में 249 मी. की दूरी पर पक्का रोड है, खदान क्षेत्र के अंदर कोई भी पेड स्थित नहीं है।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूकी प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।

726वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–9000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.70 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.38 लाख प्रति वर्ष ।
3. प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
सी.ई.आर मद से 70,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम भण्डारिया के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	**70,000/-**
Total	70,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर **(पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर)**	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	50
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	सीताफल, आवलॉं,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	350
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

726वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2024

2. <u>Case No 11251/2024 M/s Velji ratna Sorathia Ifra Pvt.Ltd., Director Shri Chandresh Sorthiya, Badodra Gujrat Halmukam Village Laloi, Tehsil Berasia, District Bhopal. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.023 ha. (1,00000 cum per year) (Khasra No. 36/5 Part), Village-Laloi, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP) (B2)-T.P.</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 21/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Gupta, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Chandresh Sorthiya, Director, M/s VELJI RATNA SORATHIA INFRA PRIVATE LIMITED, Badodra Gujrat Halmukam Village Laloi Tehsil Berasia District Bhopal (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	36/5 Part (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड भू–स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त)	2.023 hectare.
स्थल	Village- LALOI Tehsil- Berasia District- Bhopal (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 2350 दिनांक 17/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–1,00,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 91 दिनांक 17/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 91 दिनांक 17/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 91 दिनांक 17/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ललोई जिला भोपाल के पत्र दिनांक 10/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 91 दिनांक 17/01/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी ।	

726वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 फरवरी 2024

स्थिति	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मेरा केस नं 11251 है, जो M.P SEIAA के Application status पर 11251 सही दिख रहा है, जबकी Track Proposal esa Search करने पर 10251 के माध्यम से दिख रहा है। जो टंकण त्रुटी के कारण हो गया है, जिसके संबंध में मेने M.P SEIAA कि समक्ष में मेल के माध्यम से दिनांक 05/02/2024 को Complaint Registered कर दि गई थी। अतः आपसे निवेदन है कि SEAC मिटिंग में केस नं 10251 कि जगह 11251 पढ़ा जाए। के द्वारा 10251 के माध्यम से सेक को भेज दिया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान को अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित है। गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 225 मी. एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में 120 मी. की दूरी पर जल निकाय क्षेत्र है, उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 237 मी. की दूरी पर कच्ची रोड स्थित है, खदान क्षेत्र के अंदर कोई भी पेड स्थित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रश्नाधिन खदान को सिया से गलत नम्बर जारी हो गया था जिसे सुधार करने हेतु उनके द्वारा सिया को ई–मेल के माध्यम से सूचना दी गई है।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूकी प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–1,00000 घनमीटर/वर्ष ।
1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.76 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.63 लाख प्रति वर्ष ।
2. प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी ग्राम ललोई स्वास्थय केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी।	**1,00,000/-**
ग्राम ललोई में जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	**1,00,000/-**
Total	**2,00,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	700
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी ,** अमलताश, **एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां** (पूर्ण सुरक्षा सहित)	100
3	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	1700
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No 7341/20 M/s S.B.Granites Ltd, 614, Apex Mall, Lal Kothi, Tank Road, Dist. Jaipur, Raj. - 302015, Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 2.50 ha. (500 cum per annum) (Khasra No. 28/1) at Village- Silpatpura, Tehsil- Chandla, District- Chhatarpur (MP) (EIA)**

This is case of Granite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 28/1) at Village- Silpatpura, Tehsil- Chandla, District- Chhatarpur (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण में समिति की पूर्व की 449वीं बैठक दिनांक 24/07/20 को ग्रेनाइट–500 घनमीटर/वर्ष हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी ।

समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 एवं 582वीं बैठक दिनांक 29/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः इस प्रकरण को पुनः नस्तीबद्ध (Delist) करने हेतु अनुसंशा भेजी गई ।

सिया के पत्र क्रमांक 610 दिनांक 06/06/23 के द्वारा प्रकरण को को पुनः रिलिस्ट कर समिति को प्राप्त हुआ है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 14/07/23 को रखा गया,

प्रकरण समिति की 660वीं बैठक दिनांक 14/07/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

प्रकरण सेक की 671वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण को डिलिस्ट कर सिया को प्रेषित किया गया था ।

सिया के 828 बैठक दिनांक 08/02/2024 को प्रकरण को रिलिस्ट कर समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है, जो आज दिनांक 21/02/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ग्रेनाईट के खनन कार्य हेतु Wire Saw Cutting method का उपयोग किया जावेगा गूगल इमेज के अनुसार खदान दक्षिण दिशा में 30 मी. की दूरी पर साईट आफिस है, दक्षिण दिशा में लगभग 370 मी. की दूरी पर आबादी है, खदान क्षेत्र के अुदर लगभग 06 पेड है जिनमें से 06 पेडों को काटा जाना प्रस्तावित है जिसके एवज में 60 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगें।

During presentation PP further submitted that:-

- The subject lease area was grant to M/s S.B. Granites Ltd in the year 2017 for 30 year, which is applicable from 28.09.2017 to 28.09.2047. The mining plan was expired in year 2022 and new mining plan is approved for the period 15.10.2022 to 14.1.2027 by department of mining and geology dated 17.07.2023.
- Some pit were seen over the goggle image for which PP has submitted that Mr. Dilip Kumar Bhatewara from Indore was granted 4.45 Hectare granite lease in 1994 for 10years at same khasara no and worked in lease area till 2004 . The said lease lapsed in 2004. The portion of lapsed lease area was declared free for fresh allotment in 2007 and 2.5 hact out of said lease area was granted to M/s SB granite in year 2017, which comprised this subsidiary area and some portions of their lease of 7hectare surrendered to make this new lease. Therefore some portion of the lease area is the part of earlier lease granted to other lessee of the same area and around 0.5 Hectare out of 2.5 Hectare the mining was already having a pit exists of around 5m average thickness of previous work. The same fact is mentioned in approved mining plan . Further letter from officer of collector vide no 1037/Kanij/2023 dated 17.05.2023 also mentioned the same fact.
- The mining operations are proposed in the Southern and northern part of the applied area with 1 to 2 benches. All operations of mining will be done by development of heavy earth moving machinery with LD-4 on single shift basis
- During the proposed period, about 2008 cum of soil and 8700 cum OB will be generated and same will be dumped barrier zone of lease area.. It is proposed to develop green belt over 2.115 ha on benches, backfilled area and all along the lease boundary

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite 500. घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 22.73 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 10.96 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 8.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

SN	सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
1.	Fund to Panna National Park for wild life habitat management and wel fare of staff	05 Lacs

2	Infrastructure development at Aganwadi of Silpatpura	03 Lacs
	Total	**Rs 8.00**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5532 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary				
Phase	**Location**	**Name of Tree/ shrub/Herbs**	**No. of Plants**	**Remark**
1st and 2nd year	Along with barrier zone having area of 0.30ha	Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Khamar and other Seeds of local species local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	**600**	Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility
Along with Mining Operation	Over bench area and backfilled area	Karanj, Jangal Jalebi, White Kastar, Neem, Chiroli, Katang Bans, Khamar, and other local species etc.	**3600**	Within lease area which will be fenced
1st year	Road Side (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	Mango, Kathal, Neeem, Jamun and other local species etc. With Tree Gaurd	**332**	With trees guard and 4ft saplings
1st year	village distribution	Mango, Leman, Kathal, Munga, Neeem, Sitafal, Jamun and other local species etc.	**1000**	
		Total	**5532**	

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. **<u>Case No 9099/22 Shri Rajesh Bahadur Singh, 141, Ghuman, Neem Ke Paas, Ghuman Kalan, Dist. Rewa, MP - 486556, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in</u>**

an area of 1.80 ha. (15876 cum per annum) (Khasra No. 1042/4), Village - Ghuman Kalan, Tehsil - Jawa, Dist. Rewa (MP) (EIA)

प्रकरण समिति की 566वीं बैठक क्रमांक 566वीं दिनांक 23/04/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था परियोजना प्रस्तावक उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित किया गया था ।

सिया की 828वीं बैठक दिनांक 08/02/24 के प्रकरण को रिलिस्ट कर समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है, जो आज दिनांक 21/02/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश बहादुर सिंह, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, ऑनलाईन मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व दिशा में लगभग 97 मी. की दूरी पर पक्का रोड है चूकी वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

5. **Case No 10023/2023 Shri Kuldeep Udainiya, Lessee, R/o 01, Simrapatti, Bahoriband, District-Katni (MP)-483330, Prior Environment Clearance for Sihora Stone Quarry in an area of 3.65 ha. (24997 cum per year) (Khasra No. 28 Part), Village-Sihora, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)**

सिया की 828 वीं बैठक दिनांक 08/02/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

"प्रस्तावित खदान वर्जन पहाडी पर स्थित है एवं उक्त पहाडी भूमेश्वर महादेव की प्राकृतिक शिवलिंग के नाम से परिलक्षित हो रही है, अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर, जबलपुर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि प्राकृतिक भूमेश्वर महादेव के नाम से परिलक्षित वर्जन पहाडी पर खनन के हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं "

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 21/02/24 को रखा गया । समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 663वीं बैठक दिनांक 27/07/23 में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज द्वारा दिनांक 20/07/23 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये ।

समिति द्वारा सिया की 828 वीं बैठक दिनांक 08/02/2024 के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरणीय सलाहकार को निर्देशित किया कि जिला कलेक्टर, जबलपुर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि प्राकृतिक भूमेश्वर महादेव के नाम से परिलक्षित वर्जन पहाडी पर खनन के हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं।

6. <u>Case No 10177/2023 Shri Mukesh Verma, Owner, R/o Near Saint Anees School, Chanakyapuri, District-Sehore (MP)-466001, Prior Environment Clearance for Pagrawad Kalan Crusher Stone Quarry Project in an area of 4.00 ha. (25725 TPA) (Khasra No. 2/1, 2/5, 2/8, 2/9), Village-Pagrawad Kalan, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)</u> (DEIAA to SEIAA)

सिया की 829 वीं बैठक दिनांक 09/02/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

"प्रस्तावित खदान के 500 मी. परिधि में एक अन्य खदान प्रकरण क्रमांक 8990/22 रकबा 2.0 हे. परिलक्षित है जिसकों मिलाकर कुल रकबा 6.0 हे. होता है जिसके अनुसार प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रकरण में जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 468 दिनांक 25/05/2023 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मी परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होना नहीं बताया गया है। अतः पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 21/02/24 को रखा गया । समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 709 वीं बैठक दिनांक 04/01/24 में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था,

परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश वर्मा (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए । उपरोक्त सिया के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि समीपस्थ स्थित***एक अन्य खदान प्रकरण क्रमांक 8990/22*** जो देवास जिला सीमा में स्थित है एवं शाजापुर जिले के बाहर है उसे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः दोनों प्रकरण

बी–1 श्रेणी के अंतर्गत विचार करने योग्य है। समिति ने विचारोपरांत निर्णय लिया कि प्रकरण सिया को अग्रेषित किया जाता है।

7. **Case No 10642/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gurira Sand Mine in an area of 4.00 ha. (43200 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Gurira, Tehsil-Mihona, District-Bhind (MP)**

सिया की 829 वीं बैठक दिनांक 09/02/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अशांक्ष व देशांस के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर एक पक्का मेजर रोड ब्रिज परिलक्षित है अतः भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी SSMG 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 में दिये गये प्रावधान "sand and gravel shall not extracted upto a distance of 01 KM from major highways on both sides or ……down-stream side अनुसार पक्के मेजर रोड में से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 21/02/24 को रखा गया । समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 710 वीं बैठक दिनांक 05/01/24 में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था, परियोजना प्रस्तावक Shri Ramakant Pandey,Online Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, ऑनलाईन एवं सुश्री स्वाति नामदेव, कार्डिनेटर क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि पुल से लीज की दूरी लगभग 690 मी. है **एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री के लोक निमार्ण सेतु विभाग का पत्र क्रमांक 3586 दिनांक 30/10/2023 पत्र में पुल के संबंध में उल्लेख किया गया है पुल के दोनों और डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 500–500 मी. की दूरी पर कोई खनन कार्य न किया जायें।**

अतः समिति कार्यपालन यंत्री के लोक निमार्ण सेतु विभाग द्वारा दिये गये अभिमत पर सहमति व्यक्त की जाती है अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 710 वीं बैठक दिनांक 05/01/24 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

8. Case No 10294/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Pipalneriya Sand Mine in an area of 5.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 221), Village-Pipalneriya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

सिया की 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को प्रकरण के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि *शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा सिया कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक 25/11/2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30/11/2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहां गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपसिथत रहा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिये गये। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबध में अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05/01/2024 को प्रेषित किया गया है।*

प्रकरण का परीक्षण

प्रकरण को समिति की पूर्व 705 वीं बैठक दिनांक 27/12/23 को तकनीकी बिन्दु पर परीक्षण कर अनुशंसित किया गया था ।

सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध **समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।**

9. Case No 10295/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Melpipliya Sand Mine in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 105), Village- Melpipalya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

सिया की 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को प्रकरण के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि *शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा सिया कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक*

25/11/2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30/11/2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहां गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपसिथत रहा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिये गये। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबध में अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05/01/2024 को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण का परीक्षण

प्रकरण को समिति की पूर्व 705 वीं बैठक दिनांक 27/12/23 को तकनीकी बिन्दु पर परीक्षण कर अनुशंसित किया गया था ।

सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध **समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।**

10. Case No 10317/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Surjana Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (2350 cum per year) (Khasra No. 1 & 279) , Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (MP)

सिया की 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को प्रकरण के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि *शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा सिया कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक 25/11/2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30/11/2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहां गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपसिथत रहा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिये गये। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबध में अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05/01/2024 को प्रेषित किया गया है।*

प्रकरण का परीक्षण

प्रकरण को समिति की पूर्व 705 वीं बैठक दिनांक 27/12/23 को तकनीकी बिन्दु पर परीक्षण कर अनुशंसित किया गया था ।

सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध **समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।**

11. Case No 10644/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Bakud Sand Mine in an area of 0.50 ha. (3600 cum per year) (Khasra No. 35), Village-Bakud, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP).

सिया की 829 वीं बैठक दिनांक 09/02/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अशांक्ष व देशांस के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर एक पक्का मेजर रोड ब्रिज परिलक्षित है अतः भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी SSMG 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 में दिये गये प्रावधान "sand and gravel shall not extracted upto a distance of 01 KM from major highways on both sides or ……down-stream side अनुसार पक्के मेजर रोड में से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परीक्षण

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 21/02/24 को रखा गया । समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 710 वीं बैठक दिनांक 05/01/24 में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था,

परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल खण्डेलवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार/अधिकृत प्रतिनिधी श्री रूद्र प्रताप सिंह मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. द्वारा प्रस्तुत किया गया और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति ने परीक्षण दोरान पाया कि कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.रा.वि. प्राधिकारण का पत्र कमांक 2187 दिनांक 03/11/2023 खदान में स्थित रोड ब्रिज के संबंध **मे उल्लेख किया गया है कि पाथाखेडा से बाकुड मार्ग में BOX Culvert एवं बाकुड से दुल्हारा, मार्ग में पूल निर्मित है। उक्त स्वीकृत रेत खदान से रेत खनन किये जाने से विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। समिति ने पाया कि महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.रा.वि. प्राधिकारण द्वारा कोई भी दूरी का उल्लेख न करते हुये अनापत्ति दी है, अतः**

समिति का निर्णय है कि सेंड गाईड माईनिंग रूल के अनुसार दूरी छोडते हुये प्रकरण की अनुशंसा की जाती है।

अतः समिति कि कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.रा.वि. प्राधिकारण द्वारा दिये गये अभिमत पर सहमति व्यक्त की जाती है अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 710 वीं बैठक दिनांक 05/01/24 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

12. **Case No 10324/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-1 Sand Deposit in an area of 0.82 ha. (8200 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Bhanjakhedi-1, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)**

सिया की 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को प्रकरण के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि ***शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा सिया कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक 25/11/2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30/11/2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहां गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपसिथत रहा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिये गये। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबध में अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05/01/2024 को प्रेषित किया गया है।***

प्रकरण का परीक्षण

प्रकरण को समिति की पूर्व 705 वीं बैठक दिनांक 27/12/23 को तकनीकी बिन्दु पर परीक्षण कर अनुशंसित किया गया था ।

सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध **समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।**

13. **Case No 10412/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL OIC MPSMCL** (प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल (**172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Lachayara Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (6000 cum per year) (Khasra No. 03), Village Lachayara, Tehsil Shamshabad,, District-Vidisha (MP)**

सिया की 813 वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

ग्राम पंचायत लचायरा जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव कमांक–17 दिनांक 12/07/23 अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में कोई रेत ओपिन स्थिति में नहीं है न ही मौके पर कोई खदान है । पूर्व में बीच नदी से पनडुब्बी द्वारा रेत का उत्खनन् किया जाता रहा है, अतः ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देना उचित नहीं है ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 21/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र वाजपेयी, पंकज वानखड़े, खनिज निरीक्षण एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण का परीक्षण

प्रकरण को समिति की पूर्व 685 वीं बैठक दिनांक 03/10/2023 को तकनीकी बिन्दु पर परीक्षण कर अनुशंसित किया गया था ।

समिति ने प्रकरण के पुनः परीक्षण के दोरान पाया कि ग्राम पंचायत लचायरा द्वारा दिनांक 12/07/23 में रेत की अनुलब्धता के आधार पर अपना मत दिया था परन्तु जिला सर्वेक्षण रिर्पोट के आधार पर उक्त मात्रा बताई गई थी जो कि जिला स्तरीय समिति स्तर पर अध्ययन के पश्चात ही प्रस्तावित की जाती है। समिति द्वारा आज दिनांक 21/02/2024 को गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता के आधार पर पुनः परीक्षण किया गया जो कि मान्य योग्य है अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला, विदिशा के पत्र कमांक 2356 दिनांक 07/12/2023 में संलग्न ग्राम पंचायत लचायरा जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव कमांक–28 दिनांक 16/08/23 पुर्नरक्षीत अभिमत के आधार पर रेत उत्खनन की अनुशंसा पुनः की जाती है।
अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की पूर्व 685 वीं बैठक दिनांक 03/10/2023 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

14. Case No -10484/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kolhuwa Sand Mine in an area of 4.046 ha. 52,680 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kolhuwa, Tehsil-Jaitpur, District-Shahdol (MP).

सिया की 829 वीं बैठक दिनांक 09/02/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अशांक्ष व देशांस के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र खदान क्षेत्र के बीचो–बीच एक पक्का मेजर रोड ब्रिज परिलक्षित है अतः भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी SSMG 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 में दिये गये प्रावधान "sand and gravel shall not extracted upto a distance of 01 KM from major highways on both sides or ……down-stream side अनुसार पक्के मेजर रोड में से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।

<u>प्रकरण का परीक्षण</u>

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 21/02/24 को रखा गया । समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 709 वीं बैठक दिनांक 04/01/24 में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था,

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. आज दिनांक 21/02/2024 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के पत्र (**क्रमांक 4150 दिनांक 18/10/2023**) के परिपेक्ष्य में **पी.डब्ल्यू.डी विभाग का पत्र क्रमांक 4150 दिनांक 31/10/2023 के** माध्यम से अवगत कराया गया कि 500मी. दूरी छोडने पर रेत खनन से कोई आपत्ति नहीं है। समिति ने परीक्षण के उपरांत एवं **पी.डब्ल्यू.डी विभाग के अनुशंसा अनुसार** 500मी. दूरी छोडने पर 40,050 घन मी./प्रति वर्ष मात्रा की अनुशंसा की गई थी

अतः समिति द्वारा लोक निमार्ण सेतु विभाग द्वारा दिये गये अभिमत पर सहमति व्यक्त की जाती है अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 709 वीं बैठक दिनांक 04/01/24 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

15. **<u>Case No 10801/2023 Shri RAM SONI, OIC-MPSMCL</u>** (कनिष्ठ प्रबंधक जिला कार्याल (य सिंगरौली, **<u>Amarpatan, ward-02 near by Shishu Shiksha Sadan School, Sidhi (M.P.) Prior Environment Clearance for Bharuhi Sand Deposit in an area of 4.80 ha. (7200</u>**

cum per year) (Khasra No. 396P), Village- Bharuhi, Tehsil- Bahri, District- Sidhi, (M.P.)

सिया की 829 वीं बैठक दिनांक 09/02/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

"सिया द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया गया कि सेक द्वारा उत्पादन क्षमता 86,400 घन मी. प्रतिवर्ष अनुशंसित की गई है जब कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार रेत खनन की उत्पादन क्षमता 72,000 घन मी. प्रतिवर्ष अंकित है। अतः प्राधिकरण द्वारा चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।"

प्रकरण को आज दिनांक 04/01/2024 को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि टंकण त्रुटि से रेत की उत्पादन क्षमता 7200 घन मी. प्रतिवर्ष अनुशंसित हो गई है जबकि अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत क्षमता 72,000 घन मी. प्रतिवर्ष है। अतः रेत क्षमता 72000 घन मी. प्रतिवर्ष पढ़ा जावें।

16. **Case No 9271/2022 Shri Vedanand Roy, Director, M/s PACIFIC MINERALS PRIVATE LTD, Baihar Road, Balaghat (M.P.) Prior Environment Clearance for Managanese Mine in an area of 10.0 ha. (Managanese - 10559.8 Tonne per annum, Sub Grade - 586.655 Tonne per annum, Mineral Reject - 586.655 Tonne per annum) (Khasra No. Compartment No. P.O 127) Village - Laugher, Tehsil - Baihar, Dist. Balaghat, MP-EIA.**

सिया की 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

"प्रकरण में सेक द्वारा 704वीं बैठक दिनांक 19/12/2023 के कार्यवाही विवरण में प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई, मौजूदा वृक्षों की संख्या व संरक्षण योजना, प्रस्तावित वृक्षारोपण की जानकारी एवं पर्यावरण संवेदनशीलता की सिथति के बारे में स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है। खदान वन क्षेत्र में स्थित है जिसमें फारेस्ट क्लियरेंस प्राप्त है अथवा नही के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया

है। इसी प्रकार माईनिंग प्लान की वैद्यता भी समाप्त हो गई है इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रिवाईस्ड माईनिंग प्लान प्राप्त कर अनुशंसा किया जाना उचित होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जायें।"

आज दिनांक 21/02/24 के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक ***704वीं बैठक दिनांक 19/12/2023*** में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था।

पर्यावरणीय सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक श्री वेदानन्द राय, ऑनलाईन द्वारा उपरोक्त सिया के कार्यवाही विवरण संबंधित बिन्दुओं के संबंध में समिति को निम्न जानकारी प्रस्तुत की :–

- This is case of underground mining of Maganese ore (Major Mineral) Deposit Mine at **atcomaprtment no 127 PO at Village – VILLAGE- LAUGHER, TEHSIL-BAIHAR, DIST. BALAGHAT (MP)** .
- The project has been proposed for the Mining of Manganese ore over forest land through mechanized method.
- The forest clearance was obtained vide no 8C/5/553/98-FCW/2671 Dated 10.12.1999 Mining will be confined to the allotted lease area for production of Mn ore – 10559.8TPA, Sub-grade Mineral – 586.655TPA & Minerals reject – 586.655 TPA.
- The proposed project is an underground and fully mechanized mining project, where mining of Manganese will be done through drilling, Blasting, Jack hameretc along with associated activities .
- The case was considered in 704th meeting of SEAC and recommends the case for environment clearance. SEIAA has considered the case in its 826rd meeting dated 23.01.2024 and sent back to SEAC for following information :

1. **Regarding conduction of public hearing of the project**

- Public hearing is conducted on 28.04.2023 at Mine Parisar, Village Laugher, Dist. Balaghat under AG Markam Additional Collector .07 comments were received for the proposed project

2. **Number of trees present at site and it conservation plan**

- The subject mine is an underground mine located over forest land. On the surface of mine , dense forest is location . Being an underground mine, none of trees is need to be cut down. Forest clearance for the subject mine was already obtained by the project proponent

3. **Proposed plantation scheme and environmental sensitive location**

- Since mine is location over forest land, no proposal of tree plantation is required within lease area over forest land . PP has already deposited of Rs 56,21,000/- on 03.02.2017 as compensation (NPV) for compensatory forestation to the forest department As per forest conservation act (letter from PCCF vide no 477/705/2017 /10-3 dated 28 march 2017. Further as per information provided by DFO vide no 4982 dated 22.06.2022 no tiger reserve, national park, sanctuary , eco sensitive zone, biodiversity of the area is located with 10 km radius .

4. Regarding validity of mining plan

- The mining plan was approved by Regional controller of mine IBM vide no MP/Balaghat/ Manganese/ RMP55/2022-23 dated 08.05.2023 which is valid from 2023-2024 to 2027-2028 till 31.03.2028.

Considering the above submission hence, committee decided to recommend the case for **grant of Prior Environment Clearance for Mining of Manganese ore in an area of 10.0 ha. (10559.8TPA, Sub-grade Mineral – 586.655TPA & Minerals Reject – 586.655 TPA) at comaprtment no 127 POat Village – Village- Laugher, Tehsil- Baihar, Dist. BALAGHAT (MP)** subject to the following special conditions:

I. Statutory compliance:

I. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and any Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

II. This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal Forest Clearance (FC) under the provision of Forest Conservation Act, 1980, if applicable to the Project.

III. Project Proponent (PP) shall obtain Consent to Operate after grant of EC and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Establish/Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.

IV. The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Department & Regulation, Act, 2015 and rules & regulations made there under PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.

V. The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned by it if applicable to the Project.

VI. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" .

VII. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for the project.

VIII. A copy of EC letter will be marked to concerned Panchayat/local NGO etc. if any from whom suggestion/representation has been received while processing the proposal.

IX. State Pollution Control Board/Committee shall be responsible for display of the EC letter at its Regional Office, District Industries Centre and Collector's office/Tehsildar's Office for 30 days.

X. The Project Authorities should widely advertise about the grant of this EC letter by printing the same in at-least two local newspapers, one of which shall be in vernacular language of the concerned area.

XI. The advertisement shall be done within 7 days of the issue of the clearance letter mentioning that the instant project has been accorded EC and copy of the EC letter is available with the State/Pollution Control Board/Committee and web site of the Ministry of Environment. Forest and Climate Change (www.environmentclearance.nic.in). A copy the advertisement and may be forwarded to the concerned MoEF&CC Regional Office for compliance and record.

XII. The Project Proponent shall inform the MoEF&CC for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership of mining lease is transferred than mining operation shall only be carried out after transfer of EC as per provision of the Para-11 of EIA Notification, 2006 as amended from time to time.

II. Air quality monitoring and preservation

I. The Project Proponent shall monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz, PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building. Canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places.

II. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of pM10 and PM2.5 are evident such as haul

road. Loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/machineries and preventive maintenance. In shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/Central Pollution Control Board.

III. Water quality monitoring and preservation

I. In case immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case mining operation involves intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA is in place before such mining operations. The permission for intersection of ground water table shall essentially be based on detailed hydro-geological study of the area.

II. Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in an around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operating in consultation with Central Ground Water Authority /State Ground Water Department.

III. The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies passing within and nearby adjacent to the mine lease and maintain its records. It shall be ensured that no obstruction and/or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year viz. pre-monsoon (April-May), monsoon (August) post monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environmental. Forest and Climate Change and its Regional Office,

IV. Project Proponent shall plan develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water/State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional office MoEFCC annually.

V. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

IV. Noise and Vibration monitoring and preservation

I. The peak particle velocity at 500 m distance or within the nearest habitation, whichever is closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.

II. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The workers engaged in operations of HEMM etc. should be provided with ear plugs/muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case in has been found that workers/personals/laborers are working without personal protective equipment.

V. Mining plan

I. The Project Proponent shall adhere to the working parameters of mining plan which was submitted at the time of EC appraisal wherein year-wise plan was mentioned for total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. NO change in basic mining proposal like mining technology, total excavation, mineral & waste production, lease area and scope of working (viz, method of mining, overburden & dump management, O.B. & dump mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc) and slope stability, roof bolt, stowing plan, ventilation, illumination shall not be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which entail adverse environmental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified after grant of EC or granted by State Govt. in the from to Short Term Permit (STP), Query license or any other name.

II. The Project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under the provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/Guidelines made there under.

III. The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavation vis-à-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan.

VI. Land Reclaimation

I. The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum progressive Mine Closure Plan.

I. The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long.

VII. Transportation

I. Vehicular emission shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

II. The Main haulage road within the mine lease should be provided with a water sprinkling arrangement for dust suppression. Other roads within the mine lease should be wetted regularly with tanker-mounted water sprinkling system. The other areas of dust generation like crushing zone, material transfer points, material yards etc. should invariably be provided with dust suppression arrangements.

VIII. Green Belt

I. The subject mine is an underground mine located over forest land. On the surface of mine , dense forest is located . Being an underground mine, **none of trees is need to be cut down.**

II. The forest clearance was obtained vide no 8C/5/553/98-FCW/2671 Dated 10.12.1999 Mining will be confined to the allotted lease area .

III. Since mine is location over forest land, no proposal of tree plantation is required within lease area over forest land . PP has already deposited of Rs 56,21,000/- on 03.02.2017 as compensation (NPV) for compensatory forestation to the forest department As per forest conservation act (letter from PCCF vide no 477/705/2017 /10-3 dated 28 march 2017. Further as per information provided by DFO vide no 4982 dated 22.06.2022 no tiger reserve, national park, sanctuary , eco sensitive zone, biodiversity of the area is located with 10 km radius .

IV. The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5 m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The proposed Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of green belt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.

V. The Project Proponent shall carryout plantation/afforestation around water body, along the roadsides, in community areas etc by planting the native species in consultation with the State Forest Department/Agriculture Department/Rural development department/Tribal Welfare Department/Gram Panchayat

IX. Public hearing and human health issues

I. The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the DGMS guidelines. The records shall be maintained properly.

II. The proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers for sanitation, Personal Hygiene. Hand washing, not to defecate in open. Women Health and Hygiene. Hand washing, not to defecate in open. Women Health and Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tobacco and alcohol use. The Proponent shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.

III. The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

IV. The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District Administration.

X. EMP& Corporate Environment Responsibility (CER)

I. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 16.54 Lakhs as capital and Rs. 16.17Lakhs as recurring cost for this project.

II. PP has proposed Rs 10 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for for wild life habitat development and staff welfare Kahna Tiger Reserve Balaghat (MP).

III. The activities and budget earmarked for Corporate Environmental Responsibility (CER) as per Ministry's O.M. No. 22-65/2017-IA.II(M) dated 01/5/2018 or as proposed by SEAC should be kept in a separate bank account. The activities proposed for CER shall be implemented in a time bound manner and annual and annual report of implementation of the same along with documentary proof viz. photography's. Purchase documents, latitude & longitude of infrastructure developed & road constructed needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually along with audited statement.

IV. Project Proponent shall keep the funds earmarked for environmental protection measures in a separate count and refrain from diverting the same for other purpose. The Year wise expenditure of such funds should be reported to the MoEFCC and its concerned Regional Office.

XI. Miscellaneous

I. The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

II. The project Proponent shall submit six monthly compliance report on the status of the implementation of the stipulated environmental safeguards to the MoEFCC& its concerned Regional Office, Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board.

III. A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-up under the control of a Senior Executive shall directly report to Head of the Organization. Adequate number of qualified Environmental Scientist and Mining Engineers shall be appointed and submit a report to RO, MoEFCC.

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
   - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
   - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
   - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
   - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
   - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
   - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
   - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे